

एक मंच पर नजर आए फडणवीस, उद्धव और राज ठाकरे

सीएम बोले-इसमें हैरानी की बात नहीं, यह महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में गुरुवार को एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। यह कार्यक्रम 75 कार्टूनिस्टों के काम और उनके परिचय पर आधारित पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजित किया गया था। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हमेशा से अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बातचीत और आपसी मेलजोल की परंपरा रही है। इस दौरान फडणवीस ने कहा- मुझे नहीं पता कि कुछ लोग हमें एक मंच पर देखकर हैरान क्यों हुए। हम हैरान नहीं हैं। यह महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है।



अलग-अलग पार्टियों के नेता एक ही कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, साथ में हंस सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा- 2019 तक जब भी उद्धवजी मुझे बुलाते थे, मैं जाता था। 2019 के बाद उन्होंने फोन नहीं किया। मैं

इंतजार कर रहा था। गौरतलब है कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद साझा करने के मुद्दे पर भाजपा और अविभाजित शिवसेना के बीच गठबंधन टूट गया था। इसके बाद दोनों दल एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गए।

राज ठाकरे बोले-कुछ मंच राजनीति से अलग होते हैं

वहीं, राज ठाकरे ने कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि तीनों नेता आज एक मंच पर कैसे आ गए। कुछ मंच ऐसे होते हैं, जहां सभी लोग राजनीति को अलग रखकर एक साथ आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में राजनीति के बजाय कला और संस्कृति पर चर्चा होती है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि तीनों नेता आज एक मंच पर कैसे आ गए। कुछ मंच ऐसे होते हैं, जहां सभी लोग राजनीति को अलग रखकर एक साथ आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में राजनीति के बजाय कला और संस्कृति पर चर्चा होती है। इस तरह के मंचों पर अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का साथ आना स्वाभाविक है। फडणवीस ने पुस्तक 'महाराष्ट्र की हास्यरेखा' तैयार करने के लिए संपादक प्रशांत कुलकर्णी और ग्रंथाली संस्था को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संग्रह पुराने कार्टून को उनके ऐतिहासिक संदर्भों के साथ सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण काम करता है। इस दौरान फडणवीस ने मजाकिया अंदाज में याद किया कि उन्होंने राज ठाकरे से कहा था कि अगर वह कभी उनका कार्टून बनाएं, तो उनकी नाक थोड़ी बड़ी बनाएं। वहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी कार्टूनिस्ट का ब्रश उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। उन्होंने बताया कि बाल ठाकरे के निर्माणाधीन स्मारक में उनके बनाए कार्टून भी रखे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में विमोचित पुस्तक को एक अनमोल खजाना बताया, जिसमें करीब 100 वर्षों का इतिहास समेटा गया है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग कार्यक्रम अब आज होगा

राहुल गांधी बोले-यह विरोध नहीं, सविधान बचाने की लड़ाई है

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज होने वाला 'सड़क पर संसद' कार्यक्रम शनिवार को होगा। राहुल गांधी ने यह जानकारी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। राहुल ने कहा, हमने आज का कार्यक्रम बारिश के कारण कल करने का फैसला किया है। उसके बाद अगले दिन हम रामलीला मैदान पर मार्च करेंगे। हमने इसमें राजनीतिक, छात्र संगठनों और सभी लोगों से आने की अपील है। 'सड़क पर संसद' कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। पब्लिक महाभियोग में जनता या राजनीतिक दल किसी



संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ विरोध जताते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली करेगा।

एमएलसी चुनाव भाजपा ने बेईमानी से जीता

सपा नेता धर्मेन्द्र यादव ने कहा, पूरा विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा है उसे देश के लोग अब समझ गए हैं। वे समर्थन कर रहे हैं। यूपी में एमएलसी चुनाव में यह भाजपा को अहसास कराया कि वे कितना पीछे हैं। जो सीट वो जीते हैं वो जुगाड़ बेईमानी से जीते हैं। सभी सीटों पर पढ़े लिखे लोगों ने सपा को मजबूत किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हम सभी इस लड़ाई में साथ हैं। यह राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम लोगों की भी लड़ाई है। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे।

संक्षिप्त समाचार

फिर से जेल जाएंगे बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सरेंजर करने को कहा

पटना (एजेंसी)। मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंजर करने का आदेश दिया है। आज दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चार महीने में जांच पूरी करने को कहा है।



दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच में आज सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के वकील ने बताया कि उनके परिवार में 25 नवंबर को शादी है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंजर करके जेल लौटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को 4 महीने में अपनी जांच पूरी करने कहा है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी। बता दें, बिहार एमएलसी चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर जनसुराज के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने को लेकर अनंत सिंह को जदयू पार्टी से बाहर कर चुकी है। अनंत सिंह के वकील कुमार हर्षवर्धन ने बताया, अभी हमारे पास ऑर्डर की डिटेल्ड कॉपी नहीं आई है।

जामिया यूनिवर्सिटी में बीस साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव

प्रशासन ने छात्रों की बात मानी, कहा-16 जुलाई से सेशन 6 हफ्ते के अंदर चुनाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र संघ चुनाव करवाने को तैयार हो गया है। जामिया प्रशासन ने 29 अक्टूबर को एक नया ऑर्डर जारी किया है, जिसमें पहली बार टाइम-बाउंड



डेडलाइन दी गई है। प्रशासन के मुताबिक, 16 जुलाई से एकडेमिक सेशन शुरू होगा। इसके को 6 हफ्तों के भीतर स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव किए जाएंगे। सविधान पुरा करने की अंतिम तारीख 15 मई 2027 है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने स्टूडेंट्स यूनियन के सविधान को तय समयसीमा में पूरा करने को कहा है। प्रशासन ने कहा है कि 2 नवंबर से ऑफलाइन क्लासेज फिर शुरू होंगी। इसके अलावा, आंदोलन के दौरान छात्रों पर जो शो-कांज नोटिस, सस्पेंशन, रीट्रिक्शन और कैपस बैन लगाए गए थे, वे सब वापस लिए जाएंगे।

इंडियन नेवी को मिलेंगे आठ नए कॉर्बेट युद्धपोत

कैबिनेट ने 40 हजार करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्वोरिटी ने इंडियन नेवी के लिए 8 एन कॉर्बेट युद्धपोत बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 40 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इन युद्धपोतों में 70 फीसदी से ज्यादा सामान भारत में बनाया जाएगा। इससे देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले युद्धपोत का निर्माण एक साल के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। इसे 2030 तक नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है।

इन 8 युद्धपोतों को सरकारी क्षेत्र की दो कंपनियां बनाएंगी। इनमें कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शामिल हैं। दोनों कंपनियों के साथ अगले कुछ दिनों में निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट होने की उम्मीद है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, हाल के समय में सरकार के उच्च स्तर पर मंजूरी पाने वाली यह पहली बड़ी रक्षा परियोजना है। इससे



इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी और देश में युद्धपोत बनाने को बढ़ावा मिलेगा। इन युद्धपोतों में 70 फीसदी से ज्यादा सामान भारत में बनाया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान और देश में रक्षा

उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सभी 8 युद्धपोत भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे सरकार के विजन को भी मजबूती मिलेगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, अगले 4 से 5 साल में इन युद्धपोतों की डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है।

यूपी में बीजेपी अंगद का पैर, कोई हिला नहीं सकता

शाह ने की योगी की तारीफ, कहा-माफिया खत्म किए

गृहमंत्री बोले-आपसी नाराजगी गोमती में बहाकर जाएं

लखनऊ (एजेंसी)। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ में थे। उन्होंने यूपी भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा- यूपी में बीजेपी अंगद का पैर है। उसे कोई नहीं हिला सकता है। आप कमर कस लो, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर नजर रखो। हमें फिर से सरकार बनानी है। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता को पार्टी का मालिक बताया। कहा कि यूपी में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो यहां भी यूसीसी लागू करेंगे। आप सभी नाराजगी और मनमुटाव को गोमती नदी में छोड़कर जाएं। चुनाव में बार-बार मुलाकात होगी। हिसाब पछुंगा। बही खाता अच्छा रहना चाहिए। उन्होंने कहा- राहुल बाबा की निरर्थक बकवास का जवाब यूपी में 2027 में बीजेपी की सरकार बनाकर देना है। इससे पहले, करीब 9 महीने बाद लखनऊ पहुंचे शाह का सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने स्वागत किया। बैठक में योगी और शाह अगल-बगल बैठे। यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और यूपी भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। शाह ने बैठक में विधानसभा चुनाव के रोडमैप पर बात की।



सपा और बसपा के सभी कार्यकाल से ज्यादा काम योगी ने किया

अमित शाह ने कहा- 50 लाख करोड़ का निवेश आया। 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर आए हैं। सपा और बसपा के सभी टर्म मिला लें तो हमारे योगी जी का एक टर्म उनसे ज्यादा है। कानून व्यवस्था सुधरने से निवेश आया है। निवेश से रोजगार आया है। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र ने यहां कोई कमी नहीं रखी है। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में हजारों करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। यूपी में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे नेटवर्क है। जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है।

परिश्रम की पराकाष्ठा कर 2027 में सरकार बनाएं

अमित शाह ने कहा- सरकार के सारे काम एक ओर हैं, फिर भी कार्यकर्ता का पराक्रम सबसे बड़ा है। सबसे अधिक कार्यकर्ता का समायोजन यूपी में हुआ है। अखिलेश के आने के बाद एक भी चुनाव सपा नहीं जीती। राहुल के आने के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव को अपना चुनाव बनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा कर 2027 में सरकार बनाएं। अमित शाह ने कहा- नरेंद्र मोदी ने फंड देने में कोई कमी नहीं की और योगी ने उसे जमीन पर उतारने में कमी नहीं की। लेकिन, जनता को यह बताना होगा। अखिलेश जी आपने और आपके पिता की सरकार ने क्या किया, गरीब का हक मारकर अपने परिवार और कार्यकर्ता को दिया। यूपी सरकार ने लाभार्थी ने चुन-चुन कर लाभ दिया है।

बनासकांठा में आकर कोई नहीं कहता कि आलू से सोना बनाएं

‘आलू से सोना’ पर पीएम मोदी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज

बनासकांठा (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा में कहा कि यहां का आलू दुनियाभर में मशहूर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बनासकांठा में आकर कोई नहीं कहता कि आलू से सोना बनाएं, क्योंकि यहां के लोग पहले ही आलू से सोना बना रहे हैं। मोदी की सभा में किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों की जगह चारपाइयां बिछाई गई थीं। इस पर उन्होंने कहा कि देश के लोगों के लिए यह अजूबा होगा कि एक सभा में सभी लोग चारपाई पर बैठें हैं।



हम चाहते हैं कि किसानों की गोबर से भी कमाई बढ़े

25 साल पहले यहां बिजली पानी की समस्या थी। मैं कहता था हमें बिजली पानी बचाना होगा। लोग विरोध करते थे मोदी कौन होता है जो ये बोलता है। मैं आपसे लड़ता रहा और देखिए हम कहां पहुंच गए। मैं आज फिर से कहूंगा पानी बिजली बचाना है। हम चाहते हैं कि किसानों की गोबर से भी कमाई बढ़े। गोबर और खेती के अवशेषों से बायोगैस बायो सीएनजी और जैविक खाद बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े। हमने मुफ्त टीकाकरण शुरू किया।

यूएनएससी की सीट के लिए भारत ने कर दिया बड़ा 'खेल'

बदल जाएंगे ग्लोबल समीकरण अमेरिका और चीन हैरान

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के लिए अस्थायी सीट हासिल करने के लिए भारत ने समुद्री सुरक्षा और आर्टिफिशियल को बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरिश पर्वथेनो ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईसानों की सुरक्षा को पुख्ता करना और समुद्र को सुरक्षित बनाने के लिए होना चाहिए न कि उन्हें और ज्यादा विवादित बनाने के लिए। इसके अलावा भारतीय दूत ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने और भूमिका निभाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है।



बद्रीनाथ से देहरादून लौट रहा हेलीकॉप्टर क़ैश

6 लोग थे सवार, जोशीमठ के पास हुआ हादसा

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से लौट रहे एक हेलीकॉप्टर की जोशीमठ क्षेत्र की पहाड़ी में क़ैश होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। सीएम धामी ने हादसे को लेकर दुःख जताया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ धाम से लौट रहे हेलीकॉप्टर जोशीमठ में चाई गांव के पास अचानक गायब हो गया। जिसमें पायलट समेत छह यात्री सवार थे। सेना की यूनिट ने डीएम चमोली को इस घटना के बारे में सूचना दी। जिसके बाद से प्रशासन और रेस्क्यू टीमें जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पायलट से अभी तक संपर्क

नहीं हो सका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुःख जताया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि-चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क़ैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है।



जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

आधुनिक तकनीक से जीवंत हुई जनजातीय अमर बलिदानियों की शौर्यगाथाएं

(राज्योत्सव पर विशेष आलेख)

लेखक-ईएमएस – डॉ.ओम डहरिया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में साकार हुआ जनजातीय स्वाभिमान का भव्य स्मारक

छत्तीसगढ़ की पावन धरा सदियों से त्याग, तपस्या, संघर्ष और स्वाभिमान की साक्षी रही है। यहां’ के घने जंगलों, पर्वतों और वनांचलों में स्वतंत्रता की ऐसी अनगिनत गाथाएं जन्मीं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इतिहास के पन्नों में अपेक्षित स्थान नहीं पा सके इन जनजातीय नायकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को अब एक नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और जनजातीय कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में नवा रायपुर अटल नगर में निर्मित ‘शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय’ देश में जनजातीय शौर्य, स्वाभिमान और आधुनिक डिजिटल तकनीक के अनूठे संगम के रूप में उभरा है। यह भव्य संग्रहालय केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशाल संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह अवसर केवल एक संग्रहालय के लोकार्पण का नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के संकल्प की सार्थक अभिव्यक्ति का था। लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक संग्रहालय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाली देश की विशिष्ट परियोजनाओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और ऐतिहासिक योगदान को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। यह संग्रहालय उसी सोच का साकार स्वरूप है, जिसमें विकास के साथ

अपनी जड़ों, संस्कृति और पुरखों के बलिदान को सहेजने का संकल्प निहित है। विशेष रूप से जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण प्रदेश के जनजातीय समाज के गौरव और आत्मसम्मान को नई ऊंचाई प्रदान करता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सोनाखान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने जिस साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया, वह आज भी छत्तीसगढ़ की सामूहिक चेतना में जीवित है। अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल विद्रोह नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण था। इस संग्रहालय में वीर नारायण सिंह सहित उन असंख्य जनजातीय योद्धाओं की गाथाओं को जीवंत किया गया है, जिनका संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आधारशिला बना। जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थापित इस संग्रहालय की भव्य दीर्घाएं इतिहास के उन अध्यायों से परिचित कराती हैं, जिन्हें जानना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। यहां लगभग 650 से अधिक जीवंत मूर्तिशिल्पों के माध्यम से जनजातीय संघर्षों का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह और सोनाखान विद्रोह जैसी ऐतिहासिक घटनाएं दर्शकों को जनजातीय वीरता के उस दौर में ले जाती हैं, जब सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे पुरखों ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह के लिए निर्मित विशेष दीर्घाएं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान को और व्यापक रूप में प्रस्तुत करती हैं।

इस संग्रहालय की सबसे बड़ी विशेषता इतिहास और आधुनिक तकनीक का अद्भुत समन्वय है। अत्याधुनिक वीएफएक्स तकनीक, डिजिटल प्रोजेक्शन, दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतियों और जीवंत मूर्तिशिल्पों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक स्वयं को उस कालखंड का साक्षी महसूस करते हैं। यहां इतिहास केवल पढ़ा या देखा नहीं जाता, बल्कि उसकी अनुभूति होती है। युद्धभूमि का वातावरण, वीर सेनानियों का संघर्ष, जनजातीय समाज की जीवनशैली और स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदान आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत हो उठते हैं।

सरदार पटेल: जिसकी दृढ़ता के आगे झुक गई सैंकड़ों रियासतें

(लेखक- योगेश कुमार गोयल / ईएमएस)

भारत के राजनीतिक एकीकरण के महनायक सरदार पटेल

(राष्ट्रीय एकता दिवस/सरदार पटेल जयंती (31 अक्तूबर) पर विशेष)

भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण के इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाता है। वे ऐसे महान नेता थे, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस, दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता से देश की दिशा बदल दी। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद बिखरी हुई रियासतों को एकजुट कर मजबूत भारत की नींव रखने वाले महान शिल्पकार भी थे। इसी योगदान के सम्मान में उनकी जयंती 31 अक्तूबर को देशभर में ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाई जाती है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्तूबर 1875 को गुजरात के नाडियಾದ में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे साहसी, स्वाभिमानी और मेहनती थे। आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा प्राप्त की। कानून की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की और शीघ्र ही एक सफल वकील के रूप में पहचान बना ली। लेकिन उनके मन में केवल व्यक्तिगत सफलता पाने की इच्छा नहीं थी। देश की गुलामी और आम लोगों की परेशानियां उन्हें भीतर तक प्रभावित करती थीं। महात्मा गांधी के विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सफल वकालत छोड़ दी और देशसेवा में जुट गए। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल खराब हो गई थी। इसके बावजूद अंग्रेज सरकार उनसे लगान वसूलना चाहती थी। पटेल ने किसानों को संगठित किया और लगान माफ़ी के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में किसानों ने एकजुट होकर सरकार का विरोध किया। अंततः अंग्रेज सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करना पड़ा। इस आंदोलन ने पटेल को एक जननेता के रूप में स्थापित किया। वर्ष 1928 का बारडोली सत्याग्रह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अंग्रेज सरकार ने किसानों पर लगान बढ़ा दिया

था जबकि वे पहले से ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। पटेल ने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया और शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। किसानों की एकजुटता और पटेल के दृढ़ नेतृत्व के सामने अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें ‘सरदार’ की उपाधि दी। तभी से वे सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्रता के बाद देश की रियासतों का भारत में विलय कराना था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश केवल अंग्रेजों से मुक्त नहीं हुआ था बल्कि उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। देश में 562 से अधिक छोटी-बड़ी रियासतें थी, जिनमें से कुछ भारत में शामिल होना चाहती थी जबकि कुछ स्वतंत्र रहना या पाकिस्तान में जाना चाहती थी। यदि इन रियासतों का भारत में विलय नहीं होता तो देश की एकता और सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता था। उस समय सरदार पटेल देश के उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे। उन्होंने वी.पी. मेनन के सहयोग से रियासतों के शासकों से बातचीत शुरू की। उन्होंने उन्हें समझाया कि स्वतंत्र भारत में सभी राज्यों का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा है। उन्होंने संवाद, समझदारी, कूटनीति और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णयों के माध्यम से अधिकांश रियासतों को भारत में शामिल कराया। यह कार्य आसान नहीं था लेकिन पटेल ने असाधारण धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया। जूनगढ़ और हैदराबाद का भारत में विलय उनकी राजनीतिक सूझबूझ और दृढ़ नेतृत्व के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया था जबकि वहां की अधिकांश जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। भारत सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाए और अंततः जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का प्रयास किया था। वहां राजकारणों की गतिविधियों से आम जनता में भय का माहौल था। बातचीत से समाधान नहीं निकलने पर सितंबर 1948 में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे ‘ऑपरेशन पोलो’ कहा गया। पांच दिनों के भीतर हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। इस प्रकार सरदार पटेल ने देश की

मरने के बाद कहां जाता है इंसान

सभी धर्मों में पुनर्जन्म की बात कही गयी है, यानी एक शरीर को छोड़ने के बाद इंसान दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन मृत्यु के बाद से पुनर्जन्म लेने तक जीव कहां रहती है यह एक बड़ा सवाल है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा तो जन्म लेती है और न मरती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जीव के मरने के बाद आत्मा कहां जाती है। इसका उत्तर आप जरूर जानना चाहते होंगे। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण ही एक ऐसा पुराण है जिसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को शरीर से निकाल कर ले जाने के लिए दो यमदूत आते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं उनकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है। जिनका अपने शरीर से मोह नहीं जाता है और जीवन काल में अच्छे कर्म नहीं करते हैं उन्हें यमदूत जबरदस्ती खींच कर अपने साथ ले जाते हैं। शरीर से निकलने के बाद आत्मा अंगूठे के आकार का बन जाती है।

यह दिखने में उसी प्रकार का होता है जैसा मृत व्यक्ति दिखने में होता है।

एकता के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान किया।

पटेल का योगदान केवल रियासतों के विलय तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को देश की एकता, स्थिरता और सुचारु शासन के लिए आवश्यक मानते थे। उनका विश्वास था कि एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के बिना इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखना कठिन होगा। उन्होंने इन सेवाओं को देश की प्रशासनिक रीढ़ बताते हुए इनके संरक्षण और विकास पर जोर दिया। विभाजन के समय देश में सांप्रदायिक हिंसा, विस्थापन और अपसुरक्षा का गंभीर संकट पैदा हो गया था। लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। ऐसे कठिन समय में पटेल ने राहत और पुनर्वास के कार्यों को प्राथमिकता दी। वे प्रशासन को लगातार सक्रिय रखते थे और शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।जवाहरलाल नेहरू के साथ सरदार पटेल के कई मुद्दों पर मतभेद थे लेकिन उन्होंने हमेशा देशहित को व्यक्तिगत विचारों से ऊपर रखा। पटेल का मानना था कि देश को मजबूत बनाने के लिए नेतृत्व में सहयोग और आपसी विश्वास जरूरी है। उन्होंने अपने अनुभव और प्रशासनिक क्षमता से नवगठित सरकार को स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल का जीवन सादगी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण था। वे दिखावे से दूर रहते थे और काम को सबसे अधिक महत्व देते थे। उनके लिए देशसेवा किसी पद या प्रतिष्ठा का विषय नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य थी। वे कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते थे। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान देती है। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में सरदार पटेल का निधन हो गया। वर्ष 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में गुजरात के केवडिया में उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ का लोकार्पण किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और उनके महान योगदान की याद दिलाती है।

इस आत्मा को लेकर यमदूत यमराज के पास जाते हैं। यहां उसे 24 घंटे रखा जाता है और जीवन काल में उसके द्वारा किये गये अच्छे बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा को पुनः उसी स्थान पर लाकर रख दिया जाता है जहां से यमदूत उसे लेकर जाते हैं। 13 दिनों तक इस स्थान पर रहकर आत्मा अपने शरीर का अंतिम संस्कार देखता है। इसके बाद यमदूत उसे अपने साथ लेकर पुनः यमलोक की ओर चलते हैं। इस रास्ते में आत्मा को यम की भयानक नगरी के दर्शन कराये जाते हैं। इस रास्ते में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यतानाएं सहनी पड़ती है। एक साल तक इस रास्ते में चलते हुए जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। यहां यमराज व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार नर्क, स्वर्ग अथवा दूसरी योनियों भेजते हैं। यहीं पर तय होता है कि व्यक्ति को दूसरा जन्म कब मिलेगा। जो लोग धर्मात्मा होते हैं उन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए विमान आता है जिसमें बैठकर आत्मा विष्णु लोक चली जाती है। जिन्हें विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है।

इस आत्मा को लेकर यमदूत यमराज के पास जाते हैं। यहां उसे 24 घंटे रखा जाता है और जीवन काल में उसके द्वारा किये गये अच्छे बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा को पुनः उसी स्थान पर लाकर रख दिया जाता है जहां से यमदूत उसे लेकर जाते हैं। 13 दिनों तक इस स्थान पर रहकर आत्मा अपने शरीर का अंतिम संस्कार देखता है। इसके बाद यमदूत उसे अपने साथ लेकर पुनः यमलोक की ओर चलते हैं। इस रास्ते में आत्मा को यम की भयानक नगरी के दर्शन कराये जाते हैं। इस रास्ते में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यतानाएं सहनी पड़ती है। एक साल तक इस रास्ते में चलते हुए जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। यहां यमराज व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार नर्क, स्वर्ग अथवा दूसरी योनियों भेजते हैं। यहीं पर तय होता है कि व्यक्ति को दूसरा जन्म कब मिलेगा। जो लोग धर्मात्मा होते हैं उन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए विमान आता है जिसमें बैठकर आत्मा विष्णु लोक चली जाती है। जिन्हें विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है।

कंपनी को राजनीतिक निकटता से लाभ और किसी दूसरी को नियामकीय दबाव से नुकसान होता है, तो संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत को ऐसे उद्योग चाहिए जो रोजगार दें, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ें और सामाजिक दायित्व भी निभाएं। टाटा समूह का भविष्य किसी राजनीतिक दल की जीत या हार का विषय नहीं होना चाहिए। असली जीत यी यह है, कानून सब पर समान रूप से लागू हो। अदानी-अंबानी की प्रतिस्पर्धा में टाटा की बलि चढ़ने की आशंका तभी दूर होगी, जब सरकार परदर्शिता, निष्पक्ष नियमन और कारोबारी स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करेगी। पूर्व में एनडीटीवी को लेकर जिस तरह के परिवर्तन हुए थे और एनडीटीवी का मालिकाना हक और प्रबंधन में परिवर्तन हुआ उसको लेकर भारत की कंपनियां चिंतित हैं।



हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस ने विवेक कन्नन को नियुक्त किया सीईओ

नई दिल्ली ।

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस ने विवेक कन्नन को अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की शुरुवार को घोषणा की। कन्नन 2020 में कंपनी में मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में शामिल हुए थे। वह सचिन पिळ्ळै की जगह लेंगे, जिन्होंने 29 अक्टूबर को आवास वित्त कंपनी के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। पिळ्ळै कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहेंगे। वित्तीय सेवा क्षेत्र में दो दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले कन्नन कंपनी की बाजार में मौजूदगी मजबूत करने और सतत वृद्धि को आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे।नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि उनके नेतृत्व में कंपनी अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत करेगी और ग्राहकों तथा हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य उपलब्ध कराएगी।हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है।

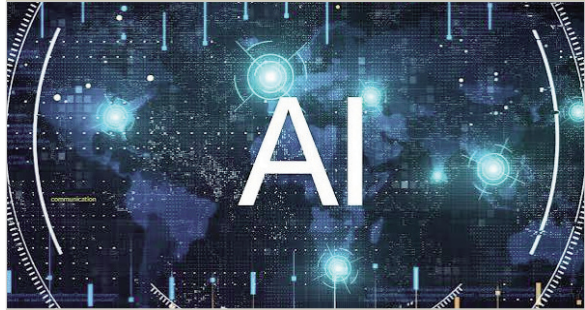
गोदरेज कंज्यूमर का मुनाफा बढ़कर 523 करोड़ पहुंचा

नई दिल्ली ।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 13.84 प्रतिशत बढ़कर 522.92 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 459.34 करोड़ रुपये था। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में गुरुवार को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल परिचालन आय 19 प्रतिशत बढ़कर 4,413.09 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3,708.19 करोड़ रुपये थी। कंपनी के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में उसकी एकीकृत बिक्री सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़ी। रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान बेचने वाली (एफएमसीजी) क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी के कर पूर्व आय (ईबीआईटीईए) में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 20.6 प्रतिशत बढ़कर 3,758.26 करोड़ रुपये रहा।

एआई के प्रभाव से अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू में 500 अरब डॉलर की गिरावट

कमजोर विज्ञापन कारोबार और एआई से राजस्व घटने की आशंका से निवेशक चिंतित



नई दिल्ली ।

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के शेयरों में 13 फीसदी से अधिक की तेज गिरावट दर्ज हुई, जिससे उसके बाजार पूंजीकरण में 500 अरब डॉलर से अधिक की कमी आई। यह अल्फाबेट के इतिहास में बाजार पूंजीकरण की सबसे बड़ी गिरावट है। तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा मुख्य राजस्व पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। अल्फाबेट ने तीसरी तिमाही में 111.2 अरब डॉलर की बिक्री दर्ज की, जो विश्लेषकों के अनुमान से कम थी। सर्च और विज्ञापन आय भी बाजार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। यह आय कुल कमाई का लगभग आधा है और एआई में बड़े निवेश के लिए अहम है। विज्ञापन कारोबार की वृद्धि दर पिछले पांच तिमाहियों में सबसे धीमी रही। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि गूगल सर्च में एआई मोड की बढ़ती लोकप्रियता से कमाई प्रभावित हुई है, क्योंकि एआई प्रश्नों से अपेक्षकृत कम राजस्व मिलता है। कंपनी इसमें विज्ञापनों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। निवेशक चिंतित हैं कि चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट और गूगल के अपने एआई फीचर्स उपभोक्ताओं को उसके सबसे अधिक कमाई वाले सर्च कारोबार से दूर कर सकते हैं। अल्फाबेट को एआई महत्वाकांक्षाओं पर भविष्य में 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक खर्च होने का अनुमान है, जिससे शीर्ष अधिकारियों पर इस भारी-भरकम निवेश को सही ठहराने का दबाव बढ़ गया है।

भारतीय कंपनियों की विदेशी उधारी बढ़ी, अगस्त में 8.13 डॉलर अरब के आवेदन

पिलफकार्ट, पीएफसी, आरईसी व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी की बड़ी उधारी की मांग

मुंबई ।

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के लिए दाखिल आवेदनों की कुल राशि अगस्त में मासिक आधार पर 5.6 प्रतिशत बढ़कर 8.13 अरब डॉलर तक पहुंच गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है,

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स ने ब्लू वॉटर लर्निंग में सौ फीसदी हिस्सेदारी खरीदी

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स ने अमेरिकी राज्य टेक्सास की ब्लू वॉटर लर्निंग में सौ फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा उसकी अनुषंगी एनआईआईटी यूएसए के जरिए 1.76 करोड़ डॉलर तक में हुआ है। इसमें अगले पांच वर्षों के दौरान प्रदर्शन के आधार पर दिए जाने वाले

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 308, निफ्टी 116 अंक उछला

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार शुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये बढ़त दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आयी है। दिन के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 308.49 अंक बढ़कर 74,459.53 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 116.35 अंक उछलकर 23,053.10 पर बंद हुआ। आज लार्ज कैप के विपरीत मिडकैप और स्मॉलकैप में दबाव रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 540.40 अंक की गिरावट के साथ 57,301.25 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 347.75 अंक की कमजोरी के साथ

18,463.60 पर बंद हुआ। बाजार को सहारा आईटी शेयरों से मिला, सूचकांकों में निफ्टी आईटी और निफ्टी हेल्थकेयर की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी फार्मा , निफ्टी सर्विसेज , निफ्टी कंजेशन और निफ्टी इन्फ्रा में भी तेजी रही। वहीं, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी मीडिया , निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएसयू बैंक , निफ्टी ऑटो गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स पैक में ट्रेट, इंडिगो, इन्फोसिस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इटरनल, टेक महिंद्रा, एचयूएल टेक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, आईटीसी, एशियन पेंट्स, टीसीएस, आईपीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, एचयूएल और टाइटन के शेयर

त्योहारों से पहले चीनी और प्याज की कीमतों में भारी उछाल

खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत 60-65, जबकि चीनी 55-60 रुपए प्रति किलो

नई दिल्ली ।

दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के नजदीक आने के बावजूद, आम जनता को चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। पिछले चार महीनों में इन दोनों आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा गया है।

खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत अभी 60-65 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में बनी हुई है, जबकि चीनी 55-60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। कुछ विशेष ब्रांड की चीनी तो 62 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ताजा मासिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। विशेषज्ञों और जानकारों के अनुसार, रबी की फसल के कम भंडार और असमान मानसून के कारण खरीफ की नई फसल की आवक को लेकर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इसी अपूर्ति में गिरावट के चलते जून से सितंबर के बीच प्याज की कीमतें करीब 85 प्रतिशत तक उछल गईं, वहीं जुलाई और अगस्त में चीनी के दामों में भी 34 प्रतिशत की भारी तेजी दर्ज की गई। प्याज की फसलों को इस साल महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्य में सूखे और फिर कमजोर मानसून की वजह से नुकसान पहुंचा है, जिससे सुरक्षित भंडार काफी कम हो गया है।

अदाणी यूरोप में 27,000 करोड़ में खरीदेंगे इवोस टर्मिनल्स

कंपनी का लक्ष्य वैश्विक समुद्री व्यापार में दबदबा बढ़ाना

मुंबई ।

अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। कंपनी ने पैन-यूरोपीय लिक्विड स्टोरेज और टर्मिनल ऑपरेटर इवोस टर्मिनल्स का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 3 अरब यूरो की बाईडिंग ऑफर पेश की है।

यह कदम अदाणी पोर्ट्स की वैश्विक विस्तार योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना है। इनिप्यो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के स्वामित्व वाली इवोस टर्मिनल्स यूरोप की सबसे बड़ी लिक्विड स्टोरेज कंपनियों में से एक है।



लाभ में रहे थे। एसबीआई, एमएंडएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, बीईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी के शेयर गिरे। वहीं

न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के 98 फीसदी विज्ञापन भ्रामक,एससीआई रिपोर्ट में खुलासा

परिषद ने 61 में से 60 विज्ञापनों को आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया

नई दिल्ली ।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की एक हालिया रिपोर्ट ने न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के विज्ञापनों में व्याप्त भ्रामक दावों का बड़ा खुलासा किया है। अ पिल फॉर थॉट शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर 2023 के बीच जांचे गए 61 विज्ञापनों में से चौकाने वाले 60 विज्ञापन एएससीआई की आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए, जो उपभोक्ताओं को झूठी उम्मीदें और गिरावट वाले बेचकर गुमराह कर रहे थे। एएससीआई की इस गहन जांच ने न्यूट्रास्युटिकल क्षेत्र में व्यापक अनियमितताओं को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार इन विज्ञापनों

में 60 दिन में छह किलो वजन घटाएं, आपकी त्वचा सात साल जवां दिखेगी और अस्थमा या पीसीओडी को उलट दें' जैसे नाटकीय दावे किए गए थे, जिनके समर्थन में कोई पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं थे। जांच में यह सामने आया कि कुल 29 विज्ञापनदाताओं ने तो अपनी आपत्तियों को चुनौती भी नहीं दी, जबकि बाकी 31 विज्ञापनदाता अपने दावों को साबित करने के लिए ठोस सबूत प्रेश करने में नाकाम रहे। रिपोर्ट में वजन प्रबंधन, त्वचा देखभाल, एंटी-एजिंग और श्वास संबंधी समस्याओं के उपचार से जुड़े दावे प्रमुखता से शामिल थे। इन विज्ञापनों में अक्सर तय समयसीमा के भीतर आश्चर्यजनक

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुरुवार को 30 पैसे की बढ़त के साथ ही 94.95 पर बंद हुआ। वहीं आज सुबह रुपया शुरुवार को शुरुआती कारोबार में सात पैसे की बढ़त के साथ 95.19 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और अमेरिकी कोष बॉन्ड के प्रतिफल में गिरावट के बीच घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपये की बढ़त को सीमित रखा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पूंजी के निरंतर प्रवाह और तेल आयात का बोझ कम होने से रुपये को मजबूती मिलने का आधार तैयार होगा। डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर के निकट अवधि में 94.75 से 95.75 के बीच रहने का अनुमान है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.21 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद इसमें मजबूती आई और यह 95.19 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले सात पैसे की बढ़त है। रुपया गुरुवार को दो पैसे की बढ़त के साथ 95.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.27 प्रतिशत फिसलकर 101.75 पर आ गया।

न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के 98 फीसदी विज्ञापन भ्रामक,एससीआई रिपोर्ट में खुलासा

परिषद ने 61 में से 60 विज्ञापनों को आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया

परिणामों का वादा किया गया, साथ ही नाटकीय पहले और बाद की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे फेफड़ों को काले रंग से गुलाबी होते हुए दिखाना। कुछ ब्रांडों ने अपने उत्पादों को अस्थमा और सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारियों के समाधान के रूप में भी प्रस्तुत किया, यह सुझाव देते हुए कि ये प्रदूषण और धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों को उलट सकते हैं।

इसके अलावा, किसी खास सामग्री पर हुए शोध का उपयोग पूरे उत्पाद के फायदों को साबित करने के लिए किया गया, जबकि तैयार उत्पाद के विज्ञापन में बताए गए नतीजे देने के कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। एएससीआई की एक अधिकारी ने इस स्थिति पर गहरी

चिंता जताते हुए कहा कि उपभोक्ता इन उत्पादों पर विश्वास करते हैं, इसलिए विज्ञापनों में किए गए दावे उपलब्ध सबूतों के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इससे उपभोक्ता सोच-समझकर फैसले ले सकेंगे और ऐसे वादों से उनका भरोसा नहीं टूटेगा, जिनके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। रिपोर्ट ने यह भी इंगित किया कि वेल्नेस उत्पादों और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाओं के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम बढ़ सकता है। एएससीआई ने न्यूट्रास्युटिकल विज्ञापनों में दावों के समर्थन में सबूतों की कमी की बढ़ती चिंताओं के कारण स्वतः संज्ञान लेते हुए यह जांच शुरू की थी।

दवा निर्यात पहली छमाही में 4.9 फीसदी बढ़कर 16.14 अरब डॉलर

यूरोप, आसियान और लातिन अमेरिका से मजबूत मांग ने दिया सहारा

नई दिल्ली ।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भारत का दवा निर्यात सालाना आधार पर 4.9 प्रतिशत बढ़कर 16.14 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय दवा निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल) के आंकड़ों के अनुसार, यूरोपीय, आसियान और लातिन अमेरिकी बाजारों से मजबूत मांग ने इस वृद्धि को गति दी है, जबकि अमेरिका की निर्यात की रफ्तार कुछ धीमी रही। फार्मेक्सिल द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक यूरोप को निर्यात में 9.66 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जो कुल दवा निर्यात का 20.38 प्रतिशत रहा। इसी अवधि में आसियान क्षेत्र में 21.54 प्रतिशत और लातिन अमेरिका व कैरेबियाई देशों में 16.58 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। अफ्रीका को दवा निर्यात में भी 6.48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान अवधि में दर्ज 15.38 अरब डॉलर के मुकाबले एक महत्वपूर्ण उछाल है। परिषद के अे अधिकारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाओं के बड़े पैमाने पर विनिर्माण के दम पर भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में गिरावट से खरीदार असमंजस में

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और भू-राजनीतिक तनाव ने बिगाड़ा खेल

नई दिल्ली ।

धनतेरस और श्रादी के शुभ अवसर से ठीक पहले सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट ने खरीदारों को असमंजस में डाल दिया है। जनवरी में 1.75 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर को छूने वाला सोना अब 1.43 लाख रुपये के करीब आ गया है, यानी करीब 20 फीसदी की कमी। इस अप्रत्याशित गिरावट ने जहां एक ओर निवेशकों के लिए अवसर पैदा किया है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह खरीदारी का सही समय है या अभी और इंतजार करना चाहिए। सोने की कीमतों में इस बड़ी गिरावट के पीछे कई वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक कारण जिम्मेदार हैं। सबसे प्रमुख वजह अमेरिका के 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है, जो 5 फीसदी से भी ऊपर चल रही है। जब अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए इन बॉन्ड पर इतना आकर्षक और सुरक्षित रिटर्न मिलता है, तो बड़े निवेशक सोने

जैसे सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इस शिफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग घटती है और उसकी कीमत पर दबाव बनता है। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिका में बढ़ती महंगाई का डर भी सोने की चमक फीकी कर रहा है। ईरान युद्ध के तनाव के कारण महंगा हुआ कच्चा तेल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ा रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें ऊंची रखी हैं, जिससे बॉन्ड यील्ड को और बढ़ावा मिला है। जानकारों का मानना ​​है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें स्थिर नहीं होतीं और महंगाई के आंकड़े नीचे नहीं आते, तब तक यील्ड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है, जो 5 फीसदी से भी ऊपर चल रही है। इसका सीधा मतलब है कि अगले कुछ महीनों या साल भर तक सोने के भाव में आकर्षक और सुरक्षित रिटर्न मिलता है, तो बड़े निवेशक सोने

नई दिल्ली ।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने सुपर अल नीनो के कारण मौसम में संभावित बदलावों से उत्पन्न जोखिमों के बावजूद भारत के आर्थिक विकास पर अपना पूरा भरोसा जताया है। आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है, भले ही खराब मौसम से जुड़े कुछ जोखिम मौजूद हों। आईएमएफ ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुपर अल नीनो जैसी घटनाओं का असर अभी तक भारत में सीधे तौर पर दिखाई नहीं दिया है, लेकिन भविष्य में इससे फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप खाने-पीने की चीजें महंगी होने की आशंका है। आईएमएफ के संचार निदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत के सामने मौसम से जुड़े कई बड़े जोखिम मौजूद हैं, हालांकि अभी तक इनका मौजूदा आर्थिक स्थिति पर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ये जोखिम वास्तविक रूप में सामने आते हैं, तो परिवारों की खरीदारी की क्षमता

प्रभाव बढ़ाने और देश की बाह्य स्थिति मजबूत करने के लिए जून में विशेष एफसीएनआर(बी) जैसी सुविधाएं शुरू की थीं। हालांकि, मजबूत प्रतिक्रिया के कारण एफसीएनआर(बी) सुविधा 31 अगस्त को समय से पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन ईसीबी और विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉन्ड सुविधा 31 दिसंबर तक खुली है, जिससे आगे भी पूंजी प्रवाह की उम्मीद है।

ब्लू वॉटर अपने ग्राहकों को रणनीति विकसित करने, समाधान लागू करने और दीर्घकालिक सफलता के लिए जरूरी संगठनात्मक बदलावों में सहायता देती है।

प्लानो में है। यह कंपनी संगठनों को सीखने और प्रतिभा विकास से जुड़े बदलावों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करती है।

जो वैश्विक पूंजी तक कंपनियों की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है। जुलाई में यह आंकड़ा 7.69 अरब डॉलर था। अगस्त में दाखिल आवेदनों में कई प्रमुख कंपनियों की बड़ी उधारी मांग शामिल थी। तीन में पिलफकार्ट इंडरनेट ने तीन साल के लिए 1.14 अरब डॉलर का कर्ज आगे ऋण देने के लिए मांगा, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने सामान्य कारोबारी

अतिरिक्त भुगतान भी शामिल हैं। एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स ने अमेरिका के टेक्सास स्थित ब्लू वॉटर लर्निंग में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 167 करोड़ रुपये में हासिल की है। कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एनआईआईटी (यूएसए) के माध्यम से किया गया है। इस सौदे का कुल मूल्य 1.76 करोड़ डॉलर



टमाटर की खेती

भारत में मटर 7.9 लाख हेक्टेयर भूमि में उगाई जाती है। इसका वार्षिक उत्पादन 8.3 लाख टन एवं उत्पादकता 1029 किग्रा./हेक्टेयर है। मटर उगाने वाले प्रदेशों में उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। उत्तरप्रदेश में 4.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मटर उगाई जाती है, जो कुल राष्ट्रीय क्षेत्र का 53.7% है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 2.7 लाख हे., उड़ीसा में 0.48 लाख., बिहार में 0.28 लाख हे. क्षेत्र में मटर उगाई जाती है।



उत्पादन तकनीक

भूमि की तैयारी – मटर की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, फिर भी गंगा के मैदानी भागों की गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। मटर के लिए भूमि को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। खरीफ की फसल की कटाई के बाद भूमि की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल करके 2-3 बार हेरो चलाकर अथवा जुताई करके पाटा लगाकर भूमि तैयार करनी चाहिए। धान के खेतों में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना जरूरी है।

फसल पद्धति- सामान्यतः मटर की फसल, खरीफ ज्वार, बाजरा, मक्का, धान और कपास के बाद उगाई जाती है। मटर, गेहूँ और जौ के साथ अंतः पसल के रूप में भी बोई जाती है। हरे चारे के रूप में जई और सरसों के साथ इसे बोया जाता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में इसकी उतैरा विधि से बुआई की जाती है।

बीजोपचार – उचित राजोबियम संवर्धक (कल्चर) से बीजों को उपचारित करना उत्पादन बढ़ाने का सबसे सरल साधन है। दलहनी फसलों में वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की क्षमता जड़ों में स्थित ग्रथिकाओं की संख्या प र

अमेरिका की न्यूक्लियर लैब में आग से हड़कंप, इमरजेंसी घोषित



वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य में एक बड़े न्यूक्लियर सेंटर की लैब में आग लगने के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई. यह आग ऐकन शहर के पास स्थित सवाना रिवर साइट परिसर की सवाना रिवर नेशनल लेबोरेटरी में लगी. अधिकारियों के मुताबिक, आग शाम 5 बजकर 39 मिनट पर लगी. इसके बाद आपातकालीन कार्रवाई शुरू की गई. करीब दो घंटे बाद आग बुझा दी गई. अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित इमारत के बाहर रेडियोएक्टिव महतरियल फैलने की कोई सूचना नहीं है. एहतियात के तौर पर केंद्र के एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए हैं और बाहर से आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है. लैब के आसपास रेल, नदी और हवाई रास्तों से होने वाली आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है. घटना से प्रभावित इलाकों में मौजूद जिन कर्मचारियों की जरूरत आग बुझाने या केंद्र को बंद करने के काम में नहीं है, उन्हें अपनी जगह पर ही सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है. केंद्र के अधिकारी हालात संभालने की कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं. राज्य और स्थानीय प्रशासन की संबंधित एजेंसियों को भी घंटे का जानकारी दे दी गई है. स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे रेडियो और टीवी पर खबरों के जरिए ताजा जानकारी लेते रहें.

स्पेन में ट्रेन हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़का-पुलिस पर बोटलें-पटाखे फेंके, परिहर्तन मंत्री से इस्तीफा मांग रहे

मैड्रिड, एजेंसी। स्पेन में बुधवार दो हाईस्पीड ट्रेनों की टक्कर में 68 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। सैकड़ों लोगों ने राजधानी मैड्रिड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परिवहन मंत्री ऑस्कर पुर्ते के इस्तीफे की मांग की है। कुछ लोगों ने उन्हें ‘मौत का मंत्री’ तक कहा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। लोगों ने पुलिस पर बोटलें और पटाखे फेंके। वहीं पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक रेल सुरक्षा सिस्टम में खराबी आई थी जिसके बाद कंट्रोल सेंटर ने एक ट्रेन को दोबारा चलने की इजाजत दी। आगे पटरी पर खड़ी दूसरी ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई। लेकिन क्षमाल सिस्टम की खराबी ही हादसे की असली वजह थी या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। परिवहन मंत्री ऑस्कर पुर्ते ने भी कहा है कि जांच के बाद हादसे की असली वजह सामने आएगी और जिम्मेदारी तय हो सकेगी।

अमेरिका ने रवांडा के रक्षा मंत्रालय पर लगाए प्रतिबंध, पूर्वी कांगो संघर्ष में दखल का आरोप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने पूर्वी कांगो में जारी संघर्ष में रवांडा की भूमिका को लेकर उसके रक्षा मंत्रालय पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की शांति की कोशिशों के बावजूद कांगो की सरकार और रवांडा समर्थित एम23 विद्रोहियों के बीच लड़ाई जारी है। ये प्रतिबंध पिछले साल के अंत में वाशिंगटन में कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स टिशसेकेदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के बीच हुए शांति समझौते के बाद लगाए गए हैं। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, अब तक इन कोशिशों का जमीनी हालात पर बहुत कम असर पड़ा है और संघर्ष जारी है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वह रवांडा के रक्षा मंत्रालय पर प्रतिबंध लगा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, रवांडा ने पूर्वी कांगो के उत्तरी किबु और दक्षिणी किबु प्रांतों में हजारों सैनिक तैनात किए हैं। ये सैनिक एम23 के साथ मिलकर अभियान चलाते हैं और इस सशस्त्र समूह को सैन्य उपकरण, जरूरी सामान, लॉजिस्टिक मदद और प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं। बयान में कहा गया कि रवांडा के अधिकारियों ने युद्ध के मैदान में आधुनिक हथियार भी तैनात किए हैं। इनमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां और संचार बाधित करने वाले उपकरण शामिल हैं। इससे पूर्वी कांगो में नागरिक विमानों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। एम23 उन करीब 100 सशस्त्र समूहों में से एक है, जो रवांडा की सीमा से लगे खनिज संपदा से भरपूर पूर्वी कांगो में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

बीजा धोखाधड़ी पर नकेल: उपराष्ट्रपति वेंस बोले- अमेरिकी वर्कर्स को हटाकर विदेशियों को रखना बर्दाश्त नहीं

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बीजा धोखाधड़ी से निपटने और उन नियोक्ताओं को चुनौती देने का अधिकार दिया है, जो अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को काम पर रख रहे हैं। उन्होंने उत्तरी कैरोलिना में अपने चुनावी भाषण में नौकरियों की सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया। किस्टन में मध्यावधि चुनाव रेली में, वेंस ने बीजा निर्यात के सख्ती से पालन को प्रशासन के उस व्यापक तर्क से जोड़ा, जिसके अनुसार सरकार को अमेरिकी कामगारों और घरेलू निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने न

तो किसी नई बीजा नीति की घोषणा की, न ही किसी नई कार्रवाई के बारे में बताया, और न ही पात्रता, आवेदन प्रक्रिया या नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों में किसी बदलाव का जिक्र किया। उनकी बातों में प्रशासन की प्राथमिकताओं की झलक थी, न कि किसी नए नियम की।

वेंस ने कहा, ‘राष्ट्रपति ने मुझे और मेरी टीम को बीजा धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी दी है, जो अमेरिकी कामगारों को नौकरी से निकालकर उनकी जगह कम वेतन वाले विदेशी नागरिकों को रख लेते हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘अमेरिकी नौकरियां



अमेरिकी नागरिकों को ही मिलनी चाहिए। वेंस ने यह नहीं बताया कि वह किस टीम की बात कर रहे थे, और न ही यह स्पष्ट किया कि ट्रंप ने उन्हें यह जिम्मेदारी कब सौंपी थी। उन्होंने किसी ऐसे नियोक्ता का नाम भी नहीं लिया जिस पर

गलत काम करने का आरोप हो, न ही किसी नियम के उल्लंघन का कोई सबूत पेश किया और न ही किसी कंपनी के खिलाफ दंड की घोषणा की। इस पूरे बयान में भारत, भारतीय सरकार या एच-1बी कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं था। इसमें अस्थायी वर्क बीजा और स्थायी निवास (परमानेंट रेजिडेंसी) पाने के रास्तों के बीच कोई अंतर भी नहीं बताया गया। अपने भाषण के अंत में, वेंस ने फिर से रोजगार के मुद्दे पर बात की। उन्होंने उन व्यवसायों को समर्थन देने का वादा किया जो अमेरिकी कामगारों में निवेश करते हैं, जबकि जो कंपनियां नौकरियां विदेशों में ले जा रही हैं, उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा,

‘मैं कारोबारी समुदाय को यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करने और अमेरिकी कामगारों में निवेश करने को तैयार हैं, तो हम आपको सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। लेकिन अगर आप अमेरिकी नौकरियों को विदेशों में ले जाना चाहते हैं, तो हम पूरी ताकत से आपका विरोध करेंगे, क्योंकि अमेरिकी नौकरियां अमेरिकी कामगारों को ही मिलनी चाहिए।’ उन्होंने इन दोनों बातों को राष्ट्रीय संप्रभुता से जोड़ते हुए कहा कि चुने हुए नेताओं को अमेरिकी नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। साथ ही, उन्हें कृषि, विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) और सशस्त्र बलों में काम करने वाले

लोगों की आजीविका की रक्षा करनी चाहिए। वेंस ने पहले के राजनीतिक नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशों में उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के उस कस्बे जैसे इलाकों को नजरअंदाज कर दिया गया, जहां वह पले-बढ़े थे। उनकी ये बातें वाशिंगटन में रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता बनाए रखने के लिए उनके चुनावी अभियान का हिस्सा थीं। उन्होंने ओहियो के मिडलटाउन में एक स्टील मिल में यूनियन वेलर के तौर पर काम करने वाले अपने दादा को याद किया और बताया कि अमेरिकी स्टील से बनी गाड़ियों पर उनके दादा को कितना गर्व होता था।

नेतन्याहू बहुमत से दूर, फिर भी सरकार बना सकते हैं

अरब पार्टियों की भी जरूरत नहीं; आइजनाकोट के पास भी सत्ता में आने के 3 रास्ते

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल में 90 प्रतिशत से ज्यादा वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इसके बाद भी सरकार बनाने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्षी नेता गाली आइजनाकोट, दोनों के गठबंधन बहुमत से दूर हैं। इजराइली संसद में 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटें चाहिए। हालांकि, नेतन्याहू इसके कम सीटें होने पर भी सरकार बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें 19 सीटों के साथ किंगमेकर बनकर उभरी अरब पार्टियों की जरूरत भी नहीं है। नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे गाली आइजनाकोट गठबंधन की उम्मीदें भी कायम हैं। 48 सीटों में आगे चल रहे इस गठबंधन के पास सरकार बनाने के 3 रास्ते हैं।

विपक्षी खेमे के सांझों का समर्थन जुटाना : नेतन्याहू विपक्षी गठबंधन में शामिल किसी पार्टी या उसके कुछ सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव देने या उनकी कुछ मांगों मानने की जरूरत पड़ सकती है। अगर विपक्षी खेमे के कुछ सांसद विश्वास मत में नेतन्याहू का समर्थन करते हैं या मतदान से दूर रहते हैं, तो उनके लिए सरकार बनाने का रास्ता आसान हो सकता है। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने चुनाव में नेतन्याहू को सत्ता से हटाने का लक्ष्य रखा था। इसलिए उनके किसी सहयोगी का नेतन्याहू के पक्ष में जाना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है। अभी किसी खास विपक्षी नेता के पाला



बदलने की पुष्टि नहीं हुई है। **राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना** : नेतन्याहू दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसमें उनके मौजूदा दक्षिणपंथी और धार्मिक सहयोगियों के साथ विपक्ष के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट या गाली आइजनाकोट जैसे नेताओं की भूमिका इस विकल्प में अहम हो सकती है। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री पद, सैन्य सेवा से जुड़े नियमों और दूसरी नीतियों पर समझौता करना होगा। आइजनाकोट और नेतन्याहू के बीच राजनीतिक मतभेद इस रास्ते की बड़ी बाधा हैं। इसके अलावा, नेतन्याहू के अति-दक्षिणपंथी सहयोगियों को भी विपक्षी नेताओं के साथ सत्ता साझा करना मंजूर होना जरूरी नहीं है।

अल्पमत सरकार चलाना : तीसरा विकल्प ऐसी सरकार बनाना है, जिसके पास अपने गठबंधन में 61 सीटें न हों, लेकिन वह विश्वास मत

हासिल कर ले। इसके लिए जरूरी नहीं कि अरब पार्टियां सरकार में शामिल हों। यदि वे मतदान से दूर रहती हैं या सरकार को खिलाफ वोट नहीं देतीं, तो संसद में मौजूद और वोट करने वाले सांसदों के हिसाब से सरकार विश्वास मत जीत सकती है। हालांकि, यह विकल्प सरकार को स्थिरता की गारंटी नहीं देता। बजट, कानून और दूसरे बड़े फैसलों के लिए नेतन्याहू को संसद में समर्थन जुटाना होगा। अगर विरोधी दल एकजुट होकर सरकार के खिलाफ वोट करते हैं, तो उनकी सरकार संकट में पड़ सकती है।

आइजनाकोट के सामने क्या रास्ते हैं : आइजनाकोट के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके खेमे की 48 सीटें बहुमत से काफी कम हैं। अरब पार्टियों की 19 सीटें जोड़ने पर नेतन्याहू विरोधी खेमे के पास सैद्धांतिक रूप से 67 सीटें हो सकती हैं। लेकिन कई यहूदी दल अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन या समझौते के खिलाफ हैं।

मॉस्को के पास यूक्रेन के ड्रोन हमले, रूसी सेना ने कई मानवरहित विमानों को मार गिराया

मॉस्को, एजेंसी। रूस की राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे करीब 30 मानवरहित हवाई विमानों (यूएवी) को रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने रूसी मीडिया को यह जानकारी दी। मेयर ने बताया कि रोकें गए ड्रोन के मलबे गिरने वाली जगहों पर आपातकालीन सेवाओं की टीमें काम कर रही हैं।

रूसी समाचार वेबसाइट इजवेंस्ट्रिया के अनुसार, नई वायु रक्षा प्रणालियों के कारण यूक्रेनी सशस्त्र बलों को अपने ड्रोन के रास्ते बदलने पड़े रहे हैं। ये प्रणालियां हवाई लक्ष्यों को रोकने से पहले ही विरोधी पक्ष की रणनीति को प्रभावित करने में सक्षम हैं। इससे पहले 15 ड्रोन को नष्ट किए जाने के बाद राजधानी की ओर बढ़ रहे 10 अन्य ड्रोन को भी वायु रक्षा प्रणालियों ने रोक लिया। इस बीच, रूस की संघीय हवाई परिवहन एजेंसी रोसाविाविएसिया ने क्षेत्र के चार प्रमुख हवाई अड्डों में से तीन पर उड़ानों को लेकर प्रतिबंध लगा दिए। इनमें वनूकोवो, डोमोडेडोवो और झुकोवस्की हवाई अड्डे शामिल हैं। झुकोवस्की में

प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जबकि अन्य दो हवाई अड्डों पर अस्थायी पाबंदियां अभी लागू हैं। क्रीव झुडिंपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉस्को क्षेत्र के निवासियों ने राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित नारो-फोर्मिस्क शहर के पास कई धमाकों की आवाज सुनने की जानकारी दी।

इस्राइल में यहूदी-अरब सरकार बनाने की मांग को लेकर तेल अवीव समेत कई जगहों पर प्रदर्शन : तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल में यहूदी-अरब सरकार बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने तेल अवीव, यरुशलम और हाइफा में प्रदर्शन किया। इस्राइली दैनिक समाचार पत्र हारेत्ज के अनुसार, यरुशलम के पेरिस स्क्वायर के तेल अवीव के मेसिला पार्क और हाइफा के यूनेस्को स्क्वायर में करीब 300 लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में ऐसे पोस्टर ले रखे थे, जिन पर ‘नदी से समुद्र तक सभी के लिए आजादी’ और ‘यहूदी-अरब सरकार के समर्थन में’ जैसे नारे लिखे थे।

ईरान पर हमले की तैयारी के बीच हेगसेथ की बड़ी कार्रवाई, पेंटागन के शीर्ष जनरल को पद से हटाया

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की चर्चा के बीच रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्विया को उनके पद से हटा दिया है। वह जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टफ में रणनीति, योजना और नीति से जुड़े अहम पद पर तैनात थे। रक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, उन्हें हटाने की वजह नहीं बताई गई है और उनकी जगह किसी नए अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं हुई है।

32 साल की सेवा के बाद पद से हटाए गए सिल्विया : सिल्विया से पहले इस पद पर रहे लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ मैक्गी को भी पिछले साल अक्टूबर में रिटायर होना पड़ा था। इस घटनाक्रम की खबर सबसे पहले द अटलांटिक ने दी थी। जॉइंट स्टफ के प्रवक्ता ने सिल्विया और उनके परिवार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने देश की 32 साल



तक सेवा की है। हालांकि, उन्हें हटाने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई। ईरान पर हमले की चर्चा के बीच फैसला : सिल्विया को ऐसे समय में हटाया गया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप कई बार ईरान के खिलाफ अभियान पूरा करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि

मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर दोबारा हमले किए जा सकते हैं। इससे पहले हालांकि, इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मामलों की जानकारी रखने वाले दो राजनयिकों के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने मध्य पूर्व के कई देशों और क्षेत्रीय सहयोगियों को संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्हें ईरान की ओर से जवाबी हमले की आशंका को लेकर भी सतर्क किया गया है। इस बीच, अमेरिका का तीसरा विमानवाहक पोत और हजारों अतिरिक्त सैनिक भी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं।

सैन्य रणनीति बनाने में अहम थी सिल्विया की भूमिका : जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टफ में छुट्ट विभाग अमेरिकी सेना की रणनीति और सैन्य योजनाएं तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। यह विभाग सैन्य अभियानों की योजना बनाने और सेना के शीर्ष



एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह बयान तब आया जब सीनेटर फ्लेवियो बोलसोनारो ने एक खुले पत्र में चुनावी धांधली का आरोप लगाया। बता दें कि रिवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर (रीनॉर्फ) में बोलसोनारो को मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा था। बोलसोनारो ने ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट (एसटीएफ) पर आरोप लगाया कि उसने मतदान का समय दो घंटे बढ़ाकर टीएसई के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि मतदान

अमेरिका में संघ की पहुंच बढ़ाएगा आरएसएस फ्रेंड्स: विदेशी एजेंट के रूप में कराया पंजीकरण

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के समर्थकों के एक समूह ‘आरएसएस फ्रेंड्स’ ने अमेरिकी न्याय विभाग में विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकरण कराया है। समूह का उद्देश्य अमेरिका में संघ के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके संबंध में गलत, अधूरी या संदर्भ से हटकर दी गई जानकारी का जवाब देना है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरएसएस फ्रेंड्स ने 27 अगस्त को विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (एफएआरए) के तहत पंजीकरण कराया। पंजीकरण दस्तावेज में, समूह ने जॉर्जिया का एक पता दिया है। उसने नई दिल्ली के केशव कुंज स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना विदेशी प्रमुख बताया है।

गलत और अधूरी जानकारी का जवाब देना भी उद्देश्य : आरएसएस फ्रेंड्स ने अपनी प्रस्तावित गतिविधियों में ऐसी जानकारी को ठीक करना या उसका जवाब देना भी शामिल किया है, जिसे समूह संघ के बारे में गलत, अधूरा या जरूरी संदर्भ से रहित मानता है। समूह ने कहा कि आरएसएस के साथ उसका कोई लिखित रोजगार, परामर्श, लॉबींग, जनसंपर्क या एजेंसी समझौता नहीं है, जिसमें काम का स्पष्ट विवरण, भुगतान या संचालन संबंधी विस्तृत निर्देश तय किए गए हों। हालांकि, समूह ने यह भी स्पष्ट किया कि

लिखित समझौते का नहीं होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि दोनों के बीच कोई संबंध, अनुरोध, समझ, समन्वय, अनुमति या निर्देश नहीं है। उसने कहा कि वह अपनी गतिविधियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों का खुलासा करेगा।

शैक्षणिक और जनसंपर्क गतिविधियों पर जोर : समूह के मुताबिक, उसकी प्रस्तावित गतिविधियां मुख्य रूप से सूचना देने, शिक्षा, जनसंपर्क और समुदाय से जुड़ाव पर केंद्रित होंगी। इसके तहत वह आम लोगों, पत्रकारों, मीडिया संस्थानों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक और नीति संस्थानों, सामुदायिक नेताओं तथा नागरिक समाज संगठनों से संवाद कर सकता है। लागू कानून के अनुरूप जरूरत पड़ने पर सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है। आरएसएस फ्रेंड्स ने संघ को भारत में स्थित स्वयंसेवी और सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन बताया है। पंजीकरण दस्तावेज में राजेंद्र सोनारिकर, जयंत पंत और देवानंद गड्डम को समूह के निदेशक मंडल का सदस्य बताया गया है।

कार्यक्रमों में भागीदारी भी प्रस्तावित गतिविधियों में शामिल समूह ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक और सूचना संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने या उनमें हिस्सा लेने को भी अपनी प्रस्तावित गतिविधियों में शामिल किया है।

ब्राजील: इलेक्टोरल कोर्ट ने कहा, ‘चुनाव कानून और संविधान के अनुरूप हुए संपन्न’



तक बढ़ाने का आदेश दिया गया। यह आदेश केवल उन मतदान केंद्रों पर लागू हुआ जो शाम 5 बजे तक खुले थे; जो केंद्र पहले ही बंद हो चुके थे, उन्हें दोबारा नहीं खोला गया। रिवार को हुए दूसरे दौर के मतदान में लुला ने बोलसोनारो को 40 लाख (4 मिलियन) से अधिक वोटों के अंतर से हराया। ब्राजीलियाई मीडिया के अनुसार, शाम 5 बजे के निर्धारित समापन समय के बाद केवल 34,300 वोट डाले गए, जो लुला की जीत के अंतर की तुलना में बहुत कम है।

अ उन्होंने टीएसई की आलोचना करते हुए कहा कि उसने मतदान का समय बढ़ाने के फैसले का बचाव तो किया, लेकिन कोई ठोस या विश्वसनीय जवाब नहीं दिया। रिवार को दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन टीम ने बताया कि वोटर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई हुई, जिसके बाद एसटीएफ ने मतदान का समय शाम 7 बजे (2200 एीएमटी)

अमेरिका पहुंचकर फ्लावियो बोलसोनारो बोले - चुनाव में धांधली हुई, मैं ब्राजील का असली नेता

मियामी, एजेंसी। ब्राजील के सीनेटर फ्लावियो बोलसोनारो अमेरिका के मियामी पहुंच गए हैं. वहां पहुंचकर उन्होंने खुद को ब्राजील का असली नेता बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने चुनाव में धांधली करके उन्हें सत्ता से दूर रखा. हालांकि, लुला ने चुनाव में करीब 45 लाख वोटों से जीत हासिल की है. फ्लावियो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी नहीं माना, जिसमें उन्हें अपने पासपोर्ट के जमा करने को कहा गया था. उन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को अमेरिका पहुंचने में मदद के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया, जिन्होंने फ्लावियो और उनके परिवार को अमेरिका आने का वीजा दिया.

पहले खुद को राष्ट्रपति बताया, फिर बदला बयान : फ्लावियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खुला लेटर पोस्ट किया. इसमें उन्होंने पहले खुद को निर्वाचित राष्ट्रपति बताया. बाद में उन्होंने यह पोस्ट हटा दी और नया लेटर जारी किया. इसमें उन्होंने खुद को ब्राजील का सही नेता बताया. उन्होंने कहा कि उनके 6 करोड़ समर्थकों और पूरे ब्राजील को जानना चाहिए कि वही देश के नेता हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी करने वाले लोग एक अपराधी संगठन का हिस्सा हैं, जिसने देश में तानाशाही कायम कर दी है. हालांकि, ब्राजील के संघीय चुनाव न्यायालय, कई देशों के नेताओं, अंतरराष्ट्रीय पर्यवेशकों और फ्लावियो की अपनी पार्टी ने लुला की जीत को मान्यता दी है. चुनाव



आयोग के प्रमुख कासियो नूनस मार्केस ने भी कहा कि चुनाव कानून और संविधान के नियमों के मुताबिक हुआ था. ट्रंप ने फ्लावियो के बयान पर कुछ कहने से इनकार किया. हालांकि, वह पहले ब्राजील के चुनाव को बहुत अजीब बता चुके हैं.

चुनाव रद्द कराने की मांग पर सफलता की उम्मीद कम : फ्लावियो ने चुनाव में धांधली का कोई सबूत नहीं दिया. उनका आरोप है कि लुला के समर्थन वाले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने रिवार को मतदान का समय दो घंटे बढ़ा दिया था. लुला की पार्टी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में वोटों को मतदान से रोकने की शिकायत की थी. दूसरी ओर, फ्लावियो की पार्टी ने भी बारिश के कारण दक्षिणी राज्यों में मतदान का समय बढ़ाने की मांग की थी. ईस्पर के प्रोफेसर पेद्रो बुग्रांस के एनालिसिस के मुताबिक, एक्सट्रा दो घंटों में 35 हजार से कम वोट पड़े. यह कुल वोटों का करीब 0.03 फीसदी था. एक्सपर्ट्स ने मुताबिक, चुनाव रद्द कराने की फ्लावियो की मांग सफल होने की संभावना बहुत कम है. फ्लावियो ने कहा कि वह ब्राजील से भागे नहीं, बल्कि खुद और परिवार को बचाने के लिए देश छोड़कर गए हैं।

दो नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप, 3 गिरफ्तार

गिर सोमनाथ, एजेंसी। जिले के कोडीनार की दो नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर मेहसाणा जिले के ऊझा तालुका स्थित उनावा गांव ले जाने और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि दोनों को मीरा दातार दरगाह में तीन दिन तक रखा गया। इस दौरान बुकां पहनाने, नाम बदलने और एक लड़की की शादी कराने की तैयारी की गई। मामले में कोडीनार पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक, कोडीनार इलाके की दोनों लड़कियों के लापता होने पर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद से तलाश शुरू की। जांच में दोनों की लोकेशन उनावा गांव में मिली। इसके बाद कोडीनार पुलिस स्थानीय पुलिस की मदद से मीरा दातार दरगाह पहुंची, जहां दोनों लड़कियां बुकां में मिलीं।

जमानत रद्द होने पर अनंत सिंह बोले— अदालत में करुंगा सरेंडर

पटना। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि वह अदालत के आदेश का पालन करते हुए सरेंडर करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और अदालत जहां तथा जब कहेगी, वह आत्मसमर्पण कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अनंत सिंह ने कहा कि वह किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि सीधे अदालत में पेश होंगे। उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय से दोबारा जमानत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता उनसे अब भी मिल रहे हैं, जबकि उनके बेटे के चुनाव लड़ने को लेकर फैसला बाद में होगा। पार्टी से निकाले जाने के सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। विधायक ने जेडीयू के नवनिर्वाचित एमएलसी नीरज कुमार पर दुलारचंद यादव की हत्या करवाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि घटना के समय वह घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर थे और उन्हें इसकी जानकारी बाद में मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि नीरज कुमार ने उनके खिलाफ मामला अदालत तक पहुंचाया। ये आरोप अनंत सिंह ने लगाए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कम दृश्यता के कारण रांची एयरपोर्ट पर उड़ाने प्रभावित, चार उड़ाने लेट और एक हुई रद्द

रांची। कम दृश्यता के कारण शुरुवार सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित रहीं। इसका असर विमानों के आगमन और प्रस्थान दोनों पर पड़ा। सुबह से ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। रांची से कई शहरों के लिए जाने वाले यात्री भी उड़ानों के परिचालन को लेकर असमंजस में रहे। वहीं दूसरे शहरों से रांची आने वाले चार विमान तय समय पर नहीं पहुंच सके। इस कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सुबह 7-15 बजे दिल्ली से रांची आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 2039 विलंबित रही। इसके बाद सुबह 7-30 बजे पुणे से आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 6484 भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंची। सुबह 9-20 बजे दिल्ली से रांची आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स 1046 और सुबह 9-30 बजे बेंगलुरु से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स 1239 भी विलंबित रही। वहीं सुबह 8-15 बजे कोलकाता से रांची आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 7461 रद्द रही। हालांकि, इस उड़ान के रद्द होने की सूचना यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी। इस कारण संबंधित उड़ान के यात्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। फिलहाल दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट अपनी उड़ान रांची लिए भरी। दूसरी ओर कम दृश्यता के कारण सुबह से विमान परिचालन प्रभावित होने से यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए इंतजार करना पड़ा।

4 नवंबर को चंडीगढ़ में सिख सम्मेलन करेगी बीजेपी !

सिख-विरोधी दंगों पर रहेगा फोकस

-इस सम्मेलन में कई सत्र होंगे, पीड़ितों को न्याय दिलाने समेत कई पहलुओं पर होगी चर्चा

चंडीगढ़, एजेंसी। बीजेपी 4 नवंबर को चंडीगढ़ में सिखों का बड़ा सम्मेलन करने की योजना बना रही है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से 1984 के सिख-विरोधी दंगों, पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके परिवारों द्वारा लड़ी गई कानूनी लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक यह सम्मेलन 1984 की हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवारों को समर्पित होगा। इसमें कई सत्र होंगे, जिनमें दंगों, उसके बाद चली कानूनी कार्यवाही और न्याय पाने की कोशिशों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी इस कार्यक्रम में सिख-विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों को आमंत्रित करने की योजना बना रही है।

सूत्रों ने बताया कि इसमें दंगों से जुड़े मामलों में पीड़ितों के परिवारों की ओर से पेश होने वाले वकील और इन मामलों में फैसला सुनाने वाले जज भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रस्तावित सम्मेलन में कई सत्र होंगे, जिनमें वका 1984 के दंगों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इनमें कानूनी कार्यवाही, न्याय के लिए संघर्ष और प्रभावित परिवारों के अनुभव शामिल होंगे। यह



कार्यक्रम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पंजाब यात्रा के समय ही आयोजित किया जा रहा है। 1984 के सिख-विरोधी दंगे पंजाब में एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा हैं। इन दंगों और उसके बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयासों को लेकर बीजेपी अक्सर कांग्रेस की आलोचना करती रही है। उम्मीद है बीजेपी इस मंच का इस्तेमाल इस मुद्दे को उजागर करने और प्रभावित परिवारों के लिए जवाबदेही और न्याय पर अपना रुख दोहराने के लिए करेगी। यह कार्यक्रम 2027 के पंजाब विधानसभा

चुनावों से पहले हो रहा है। बीजेपी राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाना चाहती है और सिख मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। पीड़ित परिवारों और कानूनी कार्यवाई से जुड़े लोगों को एक साथ मंत्री को लेकर बीजेपी समुदाय के साथ जुड़ने के साथ-साथ न्याय के मुद्दे को प्रमुखता से सामने लाना चाहती है। इस कार्यक्रम का आधिकारिक शेड्यूल, वक्ताओं की सूची और इसमें शामिल होने वाले लोगों के नामों की घोषणा अभी बाकी है।

प्रदीप पूर्णकर की हत्या के मुख्य साजिशकर्ताओं को संरक्षण दे रही महाराष्ट्र सरकार

● आदित्य ठाकरे ने लगाए आरोप, कहा- न्याय नहीं मिला तो निकालेंगे विशाल मोर्चा



मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर पार्टी नेता प्रदीप पूर्णकर की हत्या के मुख्य साजिशकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। शिवसेना (यूबीटी) के मानपाड़ा वार्ड प्रमुख प्रदीप पूर्णकर की 29 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। उन्हें पहले गोली मारी गई और फिर धारदार हथियारों से हमला किया गया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में वली के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि प्रदीप पूर्णकर की हत्या स्पष्ट रूप से राजनीतिक हत्या है। सदियों के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद कार्यवाई क्यों नहीं की जा रही है? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आरोपियों और मुख्य साजिशकर्ताओं को क्यों बचा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला, तो ठाणे में एक विशाल मोर्चा निकाला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने सवाल उठया कि ऐतिहासिक रूप से बिहार को खराब शासन के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता था, लेकिन ठाणे में स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि लोग यह कहने पर मजबूर हैं कि बिहार इससे बेहतर है। जब पूर्णकर का बेटा राम प्रभारी मंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना चाहता था, तो उसे हिरासत में ले लिया गया। जेड श्रेणी की सुरक्षा होने के बावजूद प्रभारी मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? वहीं, संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र ने देवेन्द्र फडणवीस जैसा कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ठाणे की स्थिति बीड से भी बदतर है।

योगी आदित्यनाथ ही होंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा !

लखनऊ , एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चल रहे शह और मात के खेल के बीच संभवतः पार्टी को अब यह समझ आ गया है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की नैया योगी आदित्यनाथ के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार कर सकेगी। इसीलिए तमाम विरोधाभासों के बीच पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2027 में होने वाले उउ विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का ही नेतृत्व रहेगा। उग्र भाजपा के नए प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने विधानसभा कार्य समिति के बाद चुनाव को लेकर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 365 दिन लगातार अपनी जनता के लिए एक्टिव है। उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही

अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। अमित शाह के इशारों को पुख्ता करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगी। पार्टी उनके कामकाज और विकास मॉडल को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाएगी। 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी ने संगठन और चुनावी प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से 4-सी रणनीति पर काम शुरू किया है। इसमें ओआरडीनेशन (समन्वय), कैडर, कास्ट (जातिगत समीकरण) और कैडीचेर (उम्मीदवार चयन) को प्रमुख आधार बनाया गया है। विनोद तावड़े ने संकेत दिया कि पार्टी का जोर बड़े-बड़े स्वागत समारोहों, होर्डैंस

और दिखावे की राजनीति के बजाय जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर रहेगा। बुथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और कैडर की सक्रियता को चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार बुथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है और उनकी हर पेशानियों को दूर करेगी। समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर भी विनोद तावड़े ने निशाना साधा। उन्होंने पीडीए की अपनी व्याख्या करते हुए इसे 'पराया धन अपना' बताया। बीजेपी का दावा है कि वह विपक्ष के जातिगत समीकरणों का मुकाबला विकास और पारदर्शी गवर्नेंस के मुद्दे पर करेगी।

केवल वैवाहिक मतभेद के आधार पर 24 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति नहीं- हाईकोर्ट

मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैवाहिक मतभेदों का हवाला देकर 24 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली 34 वर्षीय महिला को याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच मतभेद मात्र गर्भावस्था समाप्त करने के लिए वैध और पर्याप्त कानूनी आधार नहीं हो सकते। मामले में महिला ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उसके और पति के बीच वैचारिक मतभेद हैं। मौजूदा पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए वह बच्चे को जन्म देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसी आधार पर उसने 24 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने महिला को राहत देने से इनकार कर दिया।



शशि थरूर अब पूरी तरह राहुल

गांधी के समर्थन में आए आगे

- एक नवंबर की रैली में शामिल होने का किया ऐलान और कहा- अब चुप नहीं रह सकते
- इमरान प्रतापगढ़ी ने भी किया दिल्ली चलो का आह्वान

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की महारेली में शामिल होने की घोषणा की है। साथ ही देश के लोगों से भी रैली में पहुंचने की अपील की है। सांसद शशि थरूर ने अपने संदेश में राहुल गांधी को लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे रहने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह उठराने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। सांसद थरूर ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि



रिपोर्टों के मुताबिक देशभर में 13 करोड़ तक नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्यवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनके मुताबिक, जवाब मांगने के लिए सड़कों पर उतरने वाले नागरिकों को जवाबदेही के बजाय बैरिकेडिंग और हिरासत का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचने की अपील की है। इंडिया गठबंधन की इस रैली में वोट बचाओ और देश बचाओ अभियान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी।

यूसीसी लागू करने के लिए

नियम तैयार करने असम

सरकार ने की समिति गठित

गुवाहाटी, एजेंसी। असम सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए नियम तैयार करने एक समिति गठित की है। राजनीतिक विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी दी गई। अधिसूचना के मुताबिक आठ सदस्यीय समिति एक महीने के अंदर नियमों का मसौदा सौंप देगी। असम विधानसभा ने 27 मई को 'समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक' पारित किया था। इसका मकसद एक ऐसा समान कानूनी ढांचा तैयार करना है, जो धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सह-जीवन साथी से जुड़े मामलों को नियंत्रित करे। गृह एवं राजनीतिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय तिवारी ने 13 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा था कि विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। यह आदेश गुरुवार को मीडिया को उपलब्ध कराया। अधिसूचना के मुताबिक गृह एवं राजनीतिक विभाग के सचिव देव प्रसाद मिश्रा समिति के अध्यक्ष होंगे। इसमें कहा गया है कि समिति के सदस्यों में वित्त विशेष आयुक्त और सचिव पार्थ प्रतीम मजूमदार, विधायी सचिव गीतांजलि डी सैकिया, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास सचिव फरीदा शम्सुल और गृह एवं राजनीतिक मामलों के अतिरिक्त सचिव मुद्दुल कुमार दास शामिल हैं। असम मई में उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया था।

भारत-श्रीलंका के युद्धपोतों और नौसेना

संयुक्त रुप से किया समुद्री अभ्यास

-इसका मकसद दोनों देशों के नौसैनिकों को एक-दूसरे के अनुभवों से परिचित कराना

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने श्रीलंकाई नौसेना के साथ एक अहम समुद्री अभ्यास भी किया है। इस नौसैनिक अभ्यास में भारत के तीन बड़े समुद्री जहाज शामिल हुए। नौसेना के आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता और भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस सारथी इस अभियान का हिस्सा थे। इस दौरान दोनों नौसेनाओं ने समुद्र में अभ्यास किया। इससे एक-दूसरे के साथ तालमेल बढ़ाने और मिलकर समुद्री अभियान चलाने की क्षमता को मजबूत करने में मदद मिली।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभियान में शामिल यह भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है। नौसेना के मुताबिक 29 अक्टूबर को श्रीलंका के कोलंबो से सफल दौरा पूरा कर पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आगे खाना हुआ। कोलंबो में इस दौर का मकसद सिर्फ नौसैनिक संबंधों को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के नौसैनिकों को एक-दूसरे के अनुभवों



और कार्यप्रणाली से परिचित कराना भी था। प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के वरिष्ठ अधिकारी ने तीनों जहाजों के कमांडिंग अधिकारियों के साथ श्रीलंका नौसेना के पश्चिमी नौसैनिक क्षेत्र के कमांडर से मुलाकात की। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और समुद्री साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारतीय नौसेना के जवानों ने कोलंबो में समुद्र तट की

सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इसके अलावा, तीनों जहाजों को स्थानीय लोगों और श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए खोला गया। लोगों को जहाजों पर पहुंचकर नौसैनिकों से बातचीत करने और भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण एवं परिचालन गतिविधियों को करीब से जानने का मौका मिला। कोलंबो से विवाद के समय संयुक्त समुद्री अभ्यास हुआ। यह इस दौर का अहम पड़ाव रहा। भारतीय जहाजों और श्रीलंका के एसएलएनएस विजयबाहु ने पैसेक्स अभ्यास में हिस्सा लिया। यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी का एक और उदाहरण बना। साथ ही दोनों देशों ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और नौसैनिक क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नौसेना के मुताबिक यह भारत की महासागर परिकल्पना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य कई इलाकों में सुरक्षा और विकास को साझा प्रयासों से आगे बढ़ाना है।

खड़गे और प्रियंका गांधी ने चक्रवात अर्नब से तबाही पर जताई चिंता

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब से हुई तबाही और ओडिशा में भारी बारिश व बाढ़ से पैदा हुए हालात पर चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने और जरूरतमंदों की हरसंभव मदद करने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने शुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दोनों राज्यों में खराब मौसम से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता जताई। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं आंध्र प्रदेश में चक्रवात से तबाही झेल रहे लोगों और ओडिशा में भारी बारिश तथा बाढ़ से प्रभावित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने सभी की सुरक्षा की कामना करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव प्रयासों में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आंध्र प्रदेश में जान-माल के नुकसान और ओडिशा में जनजीवन प्रभावित होने पर दुख जताया। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने की अपील की। खड़गे ने कहा कि प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए पीएम केयर्स फंड के माध्यम से भी मदद सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संकट में फंसे लोगों की सहायता करने को कहा।



और कार्यप्रणाली से परिचित कराना भी था। प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के वरिष्ठ अधिकारी ने तीनों जहाजों के कमांडिंग अधिकारियों के साथ श्रीलंका नौसेना के पश्चिमी नौसैनिक क्षेत्र के कमांडर से मुलाकात की। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और समुद्री साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारतीय नौसेना के जवानों ने कोलंबो में समुद्र तट की

शशि थरूर अब पूरी तरह राहुल

गांधी के समर्थन में आए आगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की महारेली में शामिल होने की घोषणा की है। साथ ही देश के लोगों से भी रैली में पहुंचने की अपील की है। सांसद शशि थरूर ने अपने संदेश में राहुल गांधी को लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे रहने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह उठराने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। सांसद थरूर ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि



रिपोर्टों के मुताबिक देशभर में 13 करोड़ तक नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्यवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनके मुताबिक, जवाब मांगने के लिए सड़कों पर उतरने वाले नागरिकों को जवाबदेही के बजाय बैरिकेडिंग और हिरासत का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचने की अपील की है। इंडिया गठबंधन की इस रैली में वोट बचाओ और देश बचाओ अभियान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी।